International Journal of Information Movement *Vol. 8 Issue XI* *(March, 2024)*
Website: www.ijim.in *ISSN: 2456-0553 (online)* **Pages 32-39**

भारत में बेरोजगारी - चुनौतियाँ और संभावनाएँ

संजय कुमार
एम.ए. अर्थशास्त्र (यूजीसी नेट)
Email: sanjay.singer57@gmail.com

सारांश : बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है जिसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में बेरोजगारी की स्थिति का गहन विश्लेषण प्रदान करना है, इसकी वर्तमान स्थिति, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों, अंतर्निहित कारणों, प्रभावों और समस्या को संबोधित करने के लिए सरकारी पहलों की खोज करना है। प्रासंगिक डेटा और साहित्य की व्यापक जांच के माध्यम से, यह पत्र भारतीय संदर्भ में बेरोजगारी से निपटने से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

मुख्य शब्द : बेरोजगारी, रोजगार

1.0 परिचय :

बेरोजगारी एक बहुआयामी सामाजिक–आर्थिक मुद्दा है जिसका व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों पर समान रूप से दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति उपयुक्त नौकरी के अवसर नहीं पा पाते हैं, जिससे उत्पादक संसाधनों की बर्बादी होती है और संभावित आर्थिक ठहराव होता है। भारत के संदर्भ में बेरोजगारी का अध्ययन विशेष रूप से देश की विशाल आबादी, विविध श्रम शक्ति और समावेशी और सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करने में आने वाली अनूठी चुनौतियों के कारण महत्वपूर्ण है।

भारत, एक तेजी से विकासशील राष्ट्र के रूप में, हाल के दशकों में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी, सेवा और विनिर्माण जैसे क्षेत्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। हालाँकि, यह वृद्धि हमेशा आनुपातिक रोजगार सृजन में तब्दील नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। भारत में बेरोजगारी का मुद्दा बहुआयामी है, जो जनसांख्यिकीय बदलाव, कौशल बेमेल, तकनीकी प्रगति और संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों जैसे कारकों से प्रभावित है।

इस शोध पत्र के उद्देश्य बहुआयामी हैं। सबसे पहले, इसका उद्देश्य भारत में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करना है, जिसमें इसकी परिमाण, विभिन्न जनसांख्यिकी में वितरण और क्षेत्रीय विविधताएँ शामिल हैं। दूसरा, यह बेरोजगारी के ऐतिहासिक रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, समय के साथ श्रम बाजार को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाओं या नीतिगत निर्णयों की पहचान करता है। इसके अतिरिक्त, यह शोध पत्र बेरोजगारी के अंतर्निहित कारणों पर गहराई से विचार करेगा, इस चुनौती में योगदान देने वाले संरचनात्मक और चक्रीय दोनों कारकों की खोज करेगा। इसके अलावा, यह बेरोजगारी के दूरगामी परिणामों की जाँच करेगा, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल होंगे, और इस मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

इसके अलावा, यह शोध पत्र भारत में बेरोजगारी से निपटने के लिए लागू की गई विभिन्न सरकारी पहलों और नीतिगत उपायों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगा। उनकी प्रभावशीलता का आकलन करके और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके, शोध का उद्देश्य इस दबावपूर्ण चिंता को संबोधित करने में शामिल नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करना है।

अंततः, यह शोध पत्र प्रासंगिक डेटा, साहित्य और विशेषज्ञ दृष्टिकोणों का उपयोग करके एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करके भारत में बेरोजगारी पर चल रहे विमर्श में योगदान देना चाहता है। बेरोजगारी से निपटने से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डालकर, यह शोध पत्र देश में स्थायी रोजगार के अवसर और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने की दिशा में रणनीतिक निर्णय लेने और सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

2.0 साहित्य की समीक्षा

भारत में बेरोजगारी के मुद्दे पर विद्वानों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यापक शोध और विश्लेषण किया गया है। साहित्य की इस समीक्षा का उद्देश्य मौजूदा ज्ञान के व्यापक अवलोकन प्रदान करना है, जिसमें भारतीय संदर्भ में बेरोजगारी का अध्ययन करने में नियोजित प्रमुख निष्कर्षों, सैद्धांतिक रूपरेखाओं और पद्धतिगत दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में बेरोजगारी पर मौलिक कार्यों में से एक असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग **(एनसीईयूएस, 2009)** द्वारा ष्भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थितिष् शीर्षक वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने भारत में श्रम बाजार की गतिशीलता, रोजगार पैटर्न और नीति हस्तक्षेपों का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया। इसने अनौपचारिक रोजगार, अल्परोजगार और विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों, जैसे कि युवा और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

तेंदुलकर (2003) और मेहरोत्रा और अन्य (2012) जैसे विद्वानों ने भारत में बेरोजगारी में योगदान देने वाले संरचनात्मक और चक्रीय कारकों का व्यापक अध्ययन किया है। उनके शोध ने श्रम बाजार पर आर्थिक सुधारों, व्यापार उदारीकरण और तकनीकी प्रगति के प्रभाव की जांच की है। इन अध्ययनों ने शैक्षिक उपलब्धि और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल बेमेल पर प्रकाश डाला है, साथ ही रोजगार परिणामों को आकार देने में श्रम बाजार की कठोरता की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है।

अग्रवाल (2012) और मित्रा (2015) द्वारा किए गए अध्ययनों ने शैक्षिक प्राप्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार की संभावनाओं के बीच संबंधों का पता लगाया है। इन कार्यों ने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांगों के साथ संरेखित करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल–आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

बेरोजगारी में क्षेत्रीय असमानताओं का **चंद और श्रीवास्तव (2014) और सिराज (2017)** जैसे विद्वानों द्वारा बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। उनके शोध ने विभिन्न राज्यों में आर्थिक अवसरों के असमान वितरण और क्षेत्रीय रोजगार पैटर्न पर औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और नीति हस्तक्षेप जैसे कारकों के प्रभाव को उजागर किया है।

(नायक, 2015 आनंद और आर्य, 2019)केस स्टडी, नृवंशविज्ञान अनुसंधान और गहन साक्षात्कार सहित गुणात्मक तरीकों का भी इस्तेमाल बेरोजगार व्यक्तियों के जीवित अनुभवों और रोजगार परिणामों को आकार देने वाले सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किया गया है

(दत्ता, 2017 पपोला और साहू, 2012)पद्धतिगत रूप से, शोधकर्ताओं ने भारत में बेरोजगारी का अध्ययन करने के लिए कई तरह के दृष्टिकोण अपनाए हैं। मात्रात्मक तरीके, जैसे कि अर्थमितीय मॉडलिंग, समय–श्रृंखला विश्लेषण और प्रतिगमन तकनीक, का व्यापक रूप से श्रम बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने, बेरोजगारी के निर्धारकों की पहचान करने और नीतिगत हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया गया है ।

(नायक, 2015 आनंद और आर्य, 2019)केस स्टडी, नृवंशविज्ञान अनुसंधान और गहन साक्षात्कार सहित गुणात्मक तरीकों का भी उपयोग बेरोजगार व्यक्तियों के जीवित अनुभवों और रोजगार परिणामों को आकार देने वाले सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया है)। इसके अतिरिक्त, कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भारत में बेरोजगारी और श्रम बाजार की गतिशीलता पर व्यापक शोध और रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। इन रिपोर्टों ने बेरोजगारी चुनौतियों से निपटने के लिए मूल्यवान डेटा, विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान की हैं (ILO, 2018; विश्व बैंक, 2020 UNDP, 2021)।

3.0 शोधपद्धती

भारत में बेरोजगारी का व्यापक विश्लेषण करने के लिए, यह शोध पत्र मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों को मिलाकर एक बहु–विधि दृष्टिकोण का उपयोग करेगा। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विभिन्न डेटा स्रोतों और दृष्टिकोणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए, इस मुद्दे की समग्र समझ प्रदान करना है। भारत में बेरोजगारी परिदृश्य की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषणों को एकीकृत किया जाएगा। मात्रात्मक निष्कर्षों को गुणात्मक अंतर्दृष्टि द्वारा पूरक बनाया जाएगा, जिससे डेटा की सूक्ष्म और प्रासंगिक व्याख्या संभव होगी। इसके अतिरिक्त, गुणात्मक विश्लेषण नीतिगत सिफारिशों और रणनीतियों के विकास को सूचित करेगा, जिससे उनकी प्रासंगिकता और व्यावहारिकता सुनिश्चित होगी। शोध प्रक्रिया के दौरान, नैतिक विचारों, जैसे कि सूचित सहमति प्राप्त करना, गोपनीयता बनाए रखना और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना, को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यप्रणाली को स्थापित शोध प्रोटोकॉल और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए निष्कर्षों की वैधता, विश्वसनीयता और दोहराव सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा।

3.1 भारत में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति:

भारत में बेरोजगारी की वर्तमा न स्थिति एक जटिल और बहुआयामी तस्वीर पेश करती है, जो देश के विविध सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को दर्शाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2021–22 में किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.8%थी, जो दर्शाता है कि श्रम बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयुक्त रोजगार के अवसर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है।

हालांकि, विभिन्न जनसांख्यिकी और क्षेत्रों में बेरोजगारी का वितरण एक समान नहीं है। आयु के हिसाब से, युवा आबादी (15–29 वर्ष की आयु) 20.9% की अनुपातहीन रूप से उच्च बेरोजगारी दर का सामना करती है, जो देश के बढ़ते युवा कार्यबल के सामने रोजगार हासिल करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। इस जनसांख्यिकीय असंतुलन का देश की आर्थिक क्षमता और सामाजिक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

बेरोजगारी दरों में लैंगिक असमानताएँ भी स्पष्ट हैं, महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर (9.1%)पुरुषों (7.1%)की तुलना में अधिक है। इस असमानता को विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें लिंग भूमिकाएं, शैक्षिक अवसर और श्रम बल भागीदारी पैटर्न शामिल हैं। समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस लिंग अंतर को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, बेरोजगारी दरों में एक उल्लेखनीय शहरी–ग्रामीण विभाजन है। शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों (7.1%)की तुलना में उच्च बेरोजगारी दर (8.7%)का अनुभव होता है। इस प्रवृत्ति को शहरी केंद्रों में उद्योगों और सेवा

क्षेत्रों की एकाग्रता, साथ ही रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर नौकरी चाहने वालों के प्रवास जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

हालाँकि, विभिन्न जनसांख्यिकी और क्षेत्रों में बेरोजगारी का वितरण एक समान नहीं है। आयु के हिसाब से, युवा आबादी (15–29 वर्ष की आयु) 20.9%की अनुपातहीन रूप से उच्च बेरोजगारी दर का सामना करती है, जो देश के बढ़ते युवा कार्यबल द्वारा रोजगार प्राप्त करने में सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। इस जनसांख्यिकीय असंतुलन का देश की आर्थिक क्षमता और सामाजिक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

बेरोजगारी दरों में लैंगिक असमानताएँ भी स्पष्ट हैं, महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर (9.1%)पुरुषों (7.1%)की तुलना में अधिक है। इस असमानता को विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें लिंग भूमिकाएँ, शैक्षिक अवसर और श्रम बल भागीदारी पैटर्न शामिल हैं। समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस लैंगिक अंतर को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, बेरोजगारी दरों में एक उल्लेखनीय शहरी–ग्रामीण विभाजन है। शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों (7.1%)की तुलना में उच्च बेरोजगारी दर (8.7%)का अनुभव होता है। इस प्रवृत्ति के लिए शहरी केंद्रों में उद्योगों और सेवा क्षेत्रों की एकाग्रता, साथ ही रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर नौकरी चाहने वालों के पलायन जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

क्षेत्रीय विविधताओं में गहराई से जाने पर, कुछ राज्यों में अन्य की तुलना में काफी अधिक बेरोजगारी दर देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, राजस्थान (23.8%), झारखंड (17%), और बिहार (16.9%) जैसे राज्यों में बेरोजगारी दर चिंताजनक रूप से अधिक है, जबकि गुजरात (1.8%), छत्तीसगढ़ (2.3%), और मध्य प्रदेश (2.8%) जैसे राज्यों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। ये असमानताएँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों, औद्योगिक विकास और श्रम बाजार की गतिशीलता के असमान वितरण को दर्शाती हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अकेले बेरोजगारी दर भारत में रोजगार की स्थिति की पूरी तस्वीर पेश नहीं करती है। रोजगार की गुणवत्ता, अल्परोजगार की व्यापकता और अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका पर भी विचार किया जाना चाहिए। पीएलएफएस के अनुसार, नियोजित आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (49.6:) अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, जो अक्सर कम वेतन, नौकरी की सुरक्षा की कमी और खराब कामकाजी परिस्थितियों की विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त, छिपी हुई बेरोजगारी की घटना, जिसमें व्यक्ति कार्यरत तो हैं, लेकिन उत्पादक रूप से संलग्न नहीं हैं, श्रम बाजार परिदृश्य को और जटिल बनाती है।

बेरोजगारी की बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, इस मुद्दे में योगदान देने वाले कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकीय बदलाव, जैसे कि बढ़ती युवा आबादी और शहरीकरण, श्रम बाजार पर दबाव डालते हैं, जिससे पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सृजन आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल और श्रम बाजार की मांगों के बीच बेमेल एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, जिससे प्रभावी नौकरी मिलान और उत्पादकता में बाधा आती है।

इसके अलावा, नई प्रौद्योगिकियों और स्वचालन के आगमन ने पारंपरिक रोजगार पैटर्न को बाधित कर दिया है, जिससे कुछ क्षेत्रों में नौकरी का विस्थापन हुआ है जबकि अन्य में नए अवसर पैदा हुए हैं। इस तकनीकी बदलाव के लिए कार्यबल को विकसित करने और फिर से कुशल बनाने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है ताकि वे उभरती हुई नौकरी बाजार की मांगों के अनुकूल हो सकें।

संरचनात्मक कारक, जैसे कि आर्थिक गतिविधियों का असमान वितरण, बुनियादी ढाँचे में अंतर और नियामक ढाँचे, विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को आकार देने में भी भूमिका निभाते हैं। लक्षित नीति हस्तक्षेपों और निवेशों के माध्यम से इन संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करना समावेशी और टिकाऊ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

संक्षेप में, भारत में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति चुनौतियों और अवसरों का एक जटिल ताना–बाना प्रस्तुत करती है। जबकि समग्र बेरोजगारी दर चिंता का विषय बनी हुई है, आयु समूहों, लिंगों और क्षेत्रों में असमानताएँ विशिष्ट जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों और नीतियों की आवश्यकता को उजागर करती हैं। बेरोजगारी परिदृश्य की बारीकियों को समझकर, नीति निर्माता और हितधारक देश की मानव पूंजी का दोहन करने और इसकी पूरी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए व्यापक रणनीति विकसित कर सकते हैं।

3.2 भारत में बेरोजगारी दर: ऐतिहासिक डेटा

भारत में बेरोजगारी की समस्या को गहराई से समझने के लिए, इसके ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण करना जरूरी है। यह खंड पिछले दशक में बेरोजगारी दर की जाँच करेगा और किसी भी महत्वपूर्ण पैटर्न या उतार–चढ़ाव की पहचान करेगा। इसके अलावा, यह देश में बेरोजगारी की स्थिति पर मंदी, नीतिगत बदलाव या संरचनात्मक बदलावों जैसी प्रमुख आर्थिक घटनाओं के प्रभाव का पता लगाएगा। इन ऐतिहासिक रुझानों का अध्ययन करके, बेरोजगारी में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

यदि आप पिछले दस या 15 वर्षों की बेरोजगारी दर के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक छोटे से चार्ट में डेटा है:

तालिका : 1.1

वर्ष	बेरोज़गारी दर
2024	6.57(जनवरी 2024)
2023	8.003
2022	7.33
2021	5.98
2020	8.00
2019	5.27
2018	5.33
2017	5.36
2016	5.42
2015	5.44
2014	5.44
2013	5.42
2012	5.41
2011	5.43
2010	5.55
2009	5.54
2008	4.41

स्रोत: CM

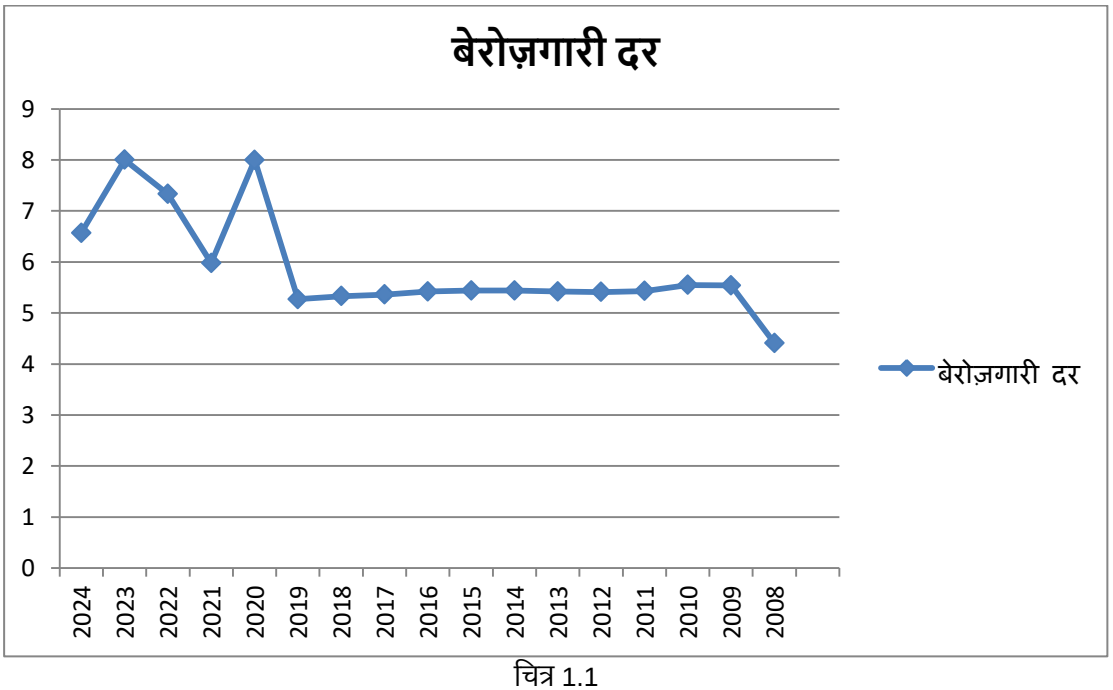

चित्र 1.1

3.3 बेरोजगारी के कारण :

भारत में बेरोजगारी के कारण बहुआयामी हैं और संरचनात्मक, चक्रीय और सामाजिक–आर्थिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध से उत्पन्न होते हैं। बेरोजगारी को कम करने और स्थायी रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी

रणनीति विकसित करने के लिए इन अंतर्निहित कारकों को समझना महत्वपूर्ण है।

3.3.1 संरचनात्मक कारक

1. कौशल बेमेल : भारत में बेरोजगारी के प्रमुख संरचनात्मक कारणों में से एक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल और श्रम बाजार की मांगों के बीच बेमेल है। शिक्षा प्रणाली अक्सर उद्योग–प्रासंगिक कौशल प्रदान करने में विफल रहती है, जिससे नौकरी चाहने वालों की योग्यता और नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के बीच एक विसंगति पैदा होती है।

2. जनसांख्यिकीय परिवर्तन: भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, जिसमें बढ़ती युवा आबादी और शहरीकरण की बढ़ती दर है, ने श्रम बाजार पर महत्वपूर्ण दबाव डाला है। हर साल कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवा नौकरी चाहने वालों की आमद नौकरी सृजन की दर से अधिक होती है, जिससे युवा बेरोजगारी के उच्च स्तर होते हैं।

3. असमान क्षेत्रीय विकास: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के असमान वितरण ने रोजगार के अवसरों में क्षेत्रीय असमानताओं में योगदान दिया है। कुछ राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त औद्योगिकीकरण, निवेश और रोजगार सृजन क्षेत्रों की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर अधिक है।

4. विनियामक और श्रम बाजार की कठोरताएँ : कठोर श्रम कानून और विनियमन, कठोर श्रम बाजार प्रथाओं के साथ मिलकर, श्रम बाजार में रोजगार सृजन और लचीलेपन में बाधा डाल सकते हैं। नियोक्ता व्यवसाय की जरूरतों के आधार पर अपने कार्यबल को समायोजित करने में कथित कठिनाइयों के कारण नए श्रमिकों को काम पर रखने में संकोच कर सकते हैं।

3.3.2 चक्रीय कारक

1. आर्थिक उतार–चढ़ाव आर्थिक मंदी, मंदी और वैश्विक मांग में उतार–चढ़ाव जैसे चक्रीय कारक, नौकरी के नुकसान और रोजगार के अवसरों में कमी का कारण बन सकते हैं। आर्थिक संकुचन की अवधि के दौरान, व्यवसाय आकार घटाने, छंटनी या भर्ती रोकने का सहारा ले सकते हैं, जिससे बेरोजगारी का स्तर बढ़ सकता है।

2. क्षेत्रीय बदलाव तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव जैसे कारकों से प्रेरित अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैटर्न में बदलाव ला सकते हैं। जबकि कुछ क्षेत्रों में नौकरी छूट सकती है, अन्य में नौकरी का सृजन हो सकता है, लेकिन अनुकूलन और कौशल परिवर्तन की गति इन बदलावों के साथ नहीं रह सकती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है।

3. स्वचालन और तकनीकी व्यवधान स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकी प्रगति के आगमन ने पारंपरिक रोजगार पैटर्न को बाधित किया है। जबकि इन प्रौद्योगिकियों में नए रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है, वे नौकरी विस्थापन का कारण भी बन सकते हैं, खासकर स्वचालन के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में।

3.3.3 सामाजिक–आर्थिक कारक

1. शैक्षणिक प्राप्ति: कम शैक्षिक प्राप्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच व्यक्तियों की रोजगार क्षमता में बाधा डाल सकती है और उनकी नौकरी की संभावनाओं को सीमित कर सकती है, खासकर औपचारिक क्षेत्र में।

2. गरीबी और अवसरों की कमी: कुछ क्षेत्रों या समुदायों में गरीबी और सीमित आर्थिक अवसर एक दुष्चक्र पैदा कर सकते हैं, जहां व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल या संसाधन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

3. भेदभाव और सामाजिक बाधाएँ : लिंग, जाति या अन्य सामाजिक कारकों के आधार पर भेदभाव कुछ समूहों के लिए रोजगार में बाधाएँ पैदा कर सकता है, नौकरी के अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमित कर सकता है और विभिन्न जनसांख्यिकी में असमान बेरोजगारी दरों में योगदान दे सकता है।

4. उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की कमी: एक कमजोर उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें वित्तपोषण तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और विनियामक बाधाएँ होती हैं, छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास में बाधा डाल सकती हैं, जो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

4.0 बेरोजगारी के प्रभाव

बेरोजगारी के दूरगामी परिणाम होते हैं जो आर्थिक प्रभावों से परे होते हैं, जो व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और राष्ट्र के समग्र सामाजिक ताने–बाने को प्रभावित करते हैं। बेरोजगारी को संबोधित करने की तात्कालिकता को पहचानने और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए व्यापक रणनीतियाँ विकसित करने के लिए इन प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है।

4.1 आर्थिक परिणाम:

1. उत्पादक क्षमता का नुकसान :बेरोजगारी उत्पादक संसाधनों और मानव पूंजी की महत्वपूर्ण बर्बादी का प्रतिनिधित्व

करती है। जब व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं, तो उनके कौशल और आर्थिक उत्पादन में संभावित योगदान का कम उपयोग होता है, जिससे समग्र उत्पादकता और आर्थिक विकास में बाधा आती है।

2. उपभोक्ता व्यय में कमी :बेरोजगार व्यक्तियों को अक्सर डिस्पोजेबल आय में कमी का अनुभव होता है, जिससे उपभोक्ता व्यय में कमी आती है। इसका व्यवसायों पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो उपभोक्ता मांग पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे संभावित रूप से और अधिक नौकरियां चली जाती हैं और आर्थिक संकुचन होता है।

3. बढ़ा हुआ राजकोषीय बोझ:बेरोजगारी लाभ, सामाजिक सहायता कार्यक्रमों और अन्य सुरक्षा उपायों पर बढ़े हुए व्यय के कारण उच्च बेरोजगारी दर सरकारी वित्त पर दबाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, कम आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप कम कर राजस्व राजकोषीय चुनौतियों को और बढ़ा सकता है।

4. प्रतिभा पलायन और प्रतिभा हानि: लंबे समय तक बेरोजगारी, विशेष रूप से अत्यधिक कुशल और शिक्षित व्यक्तियों के बीच, प्रतिभा पलायन का कारण बन सकती है क्योंकि प्रतिभाशाली कर्मचारी विदेश या अन्य क्षेत्रों में अवसरों की तलाश करते हैं, जिससे देश मूल्यवान मानव पूंजी से वंचित हो जाता है।

4.2 सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

1. गरीबी और आय असमानता: बेरोजगारी गरीबी और आय असमानता से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थिर रोजगार के बिना व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय कठिनाई, घटते जीवन स्तर और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच का अनुभव होने की अधिक संभावना है।

2. मानसिक स्वास्थ्य परिणाम : बेरोजगारी का व्यक्तियों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है, जिससे तनाव, चिंता, अवसाद और आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। ये मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ किसी व्यक्ति की रोजगार पाने और उसे सुरक्षित करने की क्षमता में बाधा डाल सकती हैं, जिससे एक दुष्चक्र बन सकता है।3.सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर जाना लंबे समय तक बेरोजगारी सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर जाने का कारण बन सकती है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक संबंध बनाए रखने, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने और अपनेपन और उद्देश्य की भावना महसूस करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं।

4. 'अंतर–पीढ़ीगत प्रभाव': बेरोजगारी के प्रभाव पीढ़ियों से परे हो सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी से प्रभावित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से गरीबी और सीमित अवसरों का चक्र जारी रह सकता है।

4.3 'दीर्घकालिक प्रभाव' :

1. 'मानव पूंजी का क्षरण': बेरोजगारी की लंबी अवधि कौशल क्षरण और अप्रचलन का कारण बन सकती है, जिससे व्यक्तियों के लिए कार्यबल में फिर से प्रवेश करना या श्रम बाजार की बदलती माँगों के अनुकूल होना मुश्किल हो जाता है।

2. 'कम आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता' : उच्च बेरोजगारी दरें किसी देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर सकती हैं, क्योंकि मानव संसाधनों का कम उपयोग और कम उत्पादकता नवाचार, उद्यमशीलता और समग्र आर्थिक विकास क्षमता में बाधा डाल सकती है।

3. 'सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता' :व्यापक बेरोजगारी, विशेष रूप से युवा आबादी के बीच, सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और अपराध दर में वृद्धि में योगदान दे सकती है, जिससे सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

4. 'अंतर–पीढ़ीगत गरीबी का जाल': लगातार बेरोजगारी और इसके संबंधित प्रभाव समुदायों और क्षेत्रों को अंतर–पीढ़ीगत गरीबी के चक्र में फंसा सकते हैं, जिससे सीमित अवसरों और आर्थिक ठहराव के दुष्चक्र से मुक्त होना मुश्किल हो जाता है।

बेरोजगारी के बहुआयामी प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक नीतियों, सामाजिक हस्तक्षेपों और लक्षित सहायता कार्यक्रमों को जोड़ता है। बेरोजगारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करके, राष्ट्र अपनी मानव पूंजी की क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और सामाजिक स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ावा दे सकते हैं।

5.0 ' सरकारी पहल और नीतिगत उपाय'

बेरोजगारी को संबोधित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न पहलों और नीतिगत उपायों को लागू किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन, श्रम बाजार सुधार और लक्षित रोजगार सृजन कार्यक्रमों सहित कई कोणों से इस मुद्दे से निपटना है।

5.1 'कौशल विकास पहल':

1. 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): 2015 में शुरू की गई, इस प्रमुख योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों

में युवाओं को उद्योग–प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पूर्व शिक्षा की मान्यता और मौद्रिक पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान करने के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाने और कुशल कार्यबल बनाने पर केंद्रित है।

2. 'कौशल भारत मिशन: 2015 में शुरू किए गए इस अम्ब्रेला कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर, उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और कौशल विकास पहलों के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र प्रदान करके एक कुशल कार्यबल तैयार करना है।

3. 'राष्ट्रीय कौशल विकास निगम : 2008 में स्थापित, छैक्ब एक सार्वजनिक–निजी भागीदारी संगठन है जो निजी क्षेत्र की पहलों को वित्त पोषण और समर्थन, योग्यता मानकों को विकसित करने और उद्योग–अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

5.2 'उद्यमिता संवर्धन:

1. 'स्टार्टअप इंडिया पहल': 2016 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वित्त तक पहुँच प्रदान करके, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, कर प्रोत्साहन प्रदान करके और इनक्यूबेशन और मेंटरशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

2. 'मुद्रा योजना': 2015 में शुरू की गई यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।

3. 'स्टैंड–अप इंडिया योजना': 2016 में शुरू की गई यह योजना कम से कम एक अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति और एक महिला उद्यमी को प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा देती है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है।

5.3 'श्रम बाजार सुधार':

1. 'श्रम संहिता: 2019–2020 में, भारत सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित कियारू मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। इन संहिताओं का उद्देश्य श्रम विनियमों को सुव्यवस्थित करना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है।

2. ''राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस): 2015 में शुरू किया गया, एनसीएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य नौकरी मिलान की सुविधा प्रदान करना, कैरियर परामर्श प्रदान करना और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

5.4 'रोजगार सृजन कार्यक्रम:

1. 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: 2005 में लागू किया गया, यह प्रमुख कार्यक्रम अकुशल मैनुअल श्रम में लगे ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। इसका उद्देश्य टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

2. 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :2008 में शुरू की गई, यह योजना बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सब्सिडी और ऋण सहायता प्रदान करती है, जिससे स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।

3. 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना : 2014 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और प्लेसमेंट के अवसरों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे उन्हें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके।

हालाँकि इन पहलों और नीतिगत उपायों ने बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता और प्रभाव अलग–अलग स्तर की सफलता के अधीन रहे हैं। भारत में बेरोजगारी की बहुआयामी चुनौतियों से निपटने में उनकी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यक्रमों का निरंतर मूल्यांकन, डेटा–संचालित निर्णय लेना और निरंतर परिशोधन आवश्यक है।

6.0 संदर्भ':

1. अग्रवाल, टी. (2012). भारत में शिक्षा का प्रतिफलरू कुछ हालिया साक्ष्य। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 24(4), 430–446.
2. आनंद, आर., और आर्य, पी. के. (2019). बेरोजगारी और मानसिक स्वास्थ्य : दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का नृवंशविज्ञान अध्ययन। जर्नल ऑफ साइकोसोशल रिसर्च, 14(2), 389–402.

3. बंगा, के. (2019). प्रौद्योगिकी द्वारा बाधित? भारत में विस्थापित नौकरी चाहने वालों के पुनः रोजगार पैटर्न। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 55(8), 1635–1654.
4. चंद, आर., और श्रीवास्तव, एस. के. (2014). ग्रामीण श्रम बाजार में परिवर्तन और प्रवास के लिए उनके निहितार्थ। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 49(3), 63–72.
5. दत्ता, पी. वी. (2017). भारत में बेरोजगारी के निर्धारकों का मॉडलिंग। अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान, 4(1), 81–91.
6. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (प्स्). (2018). भारत वेतन रिपोट: सभ्य कार्य और समावेशी विकास के लिए वेतन नीतियाँ. जिनेवा:
7. मेहरोत्रा, एस., गांधी, ए., और साहा, पी. (2012). बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 47(19), 63–73.
8. मित्रा, ए. (2015). कौशल और रोजगार:भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों का एक अनुभवजन्य अध्ययन. जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड वर्क, 28(5), 531–549.
9. असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग (2009). भारत में रोजगार की चुनौती: एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था परिप्रेक्ष्य. नई दिल्ली:भारत सरकार.
10. नायक, पी. (2015). बेरोजगारी की वास्तविकताओं की खोज: मुंबई में युवाओं के दृष्टिकोण. जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 17(2), 171–190.
11. पापोला, टी.एस., और साहू, पी.पी. (2012). भारत में रोजगार की वृद्धि और संरचना:दीर्घकालिक और सुधार के बाद का प्रदर्शन और उभरती चुनौती। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (आईएसआईडी) वर्किंग पेपर।
12. सिराज, एस. (2017). भारत में रोजगार में क्षेत्रीय असमानताएँ : एक जिला स्तरीय विश्लेषण। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, 2(2), 192–212.
13. तेंदुलकर, एस.डी. (2003). संगठित श्रम बाजार और आर्थिक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। भारतीय आर्थिक समीक्षा, 38(2), 189–224.
14. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)। (2021). भारत में सतत सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के लिए मानव पूंजी को मजबूत करना। नई दिल्ली: यूएनडीपी इंडिया।
15. वशिष्ठ, पी., और दुबे, आर. (2018). भारत में नौकरी का बदलता परिदृश्य : रोजगार पैटर्न, चुनौतियाँ और नीति निर्देश। इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 61(2), 229–248.
16. विश्व बैंक. (2020).दक्षिण एशिया में अनौपचारिकता और कोविड–19. दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस. वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक.